ई-केवाईसी नहीं कराया तो रुकेगी सब्सिडी

सब्सिडी पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं

10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे.

नई दिल्ली, 3 जुलाई. रसोई गैस (एलपीजी) उपभोक्ताओं के लिए जुलाई की शुरुआत के साथ सब्सिडी से जुड़े नियम और सख्त हो गए हैं. सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने लाभार्थियों का सत्यापन तेज कर दिया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी सब्सिडी केवल वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे.

इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है. जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून तक ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उनकी सब्सिडी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है. सरकार के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक सत्यापन (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया आधार आधारित सत्यापन पर आधारित है. इससे फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र गैस कनेक्शनों की पहचान करना आसान होगा. जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, जिन लोगों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करने की सलाह दी गई है. एलपीजी सब्सिडी के पात्रता नियम पहले की तरह लागू रहेंगे. यदि किसी परिवार की वार्षिक कर योग्य आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो वह सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकेगा. इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं की जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती या जिनका सत्यापन लंबित है, उनकी सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है.

> सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसी पात्र उपभोक्ता को परेशानी में डालना नहीं, बल्कि सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है. पिछले कुछ वर्षों में फर्जी लाभार्थियों और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाए गए हैं. ई-केवाईसी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बीएलएस ने अतियाती टेक्नोलॉजीज खरीदी

नयी दिल्ली, 03 जुलाई तकनीक आधारित डिजिटल सेवाएं देने वाली कंपनी बीएलएस ई-सर्विसेज ने बेंगलुरु की एआई आधारित बैंकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी अतियाती टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. इस अधिग्रहण के लिए कंपनी ने 157 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया है. अतियाती टेक्नोलॉजीज बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एआई आधारित डिजिटल बैंकिंग समाधान, माइक्रो-लोन प्लेटफॉर्म और गांव-गांव तक बैंकिंग पहुंचाने वाली सेवाएं उपलब्ध कराती है. कंपनी 35 से अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ काम करती है. इसके पास 25,900 से अधिक कस्टमर सर्विस प्वाइंट हैं, जोदेश के लगभग एक लाख गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाते हैं.

पीएफ के जानें कई बड़े फायदे

नई दिल्ली, 3 जुलाई. नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से हर महीने कटने वाला प्रोविडेंट फंड केवल एक अनिवार्य बचत योजना नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित यह योजना कर्मचारियों को नौकरी के दौरान और रिटायरमेंट के बाद भी कई तरह के फायदे देती है. लेकिन अधिकतर लोग इसे सिर्फ रिटायरमेंट फंड मानकर नजरअंदाज कर देते हैं.

पीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान हर महीने जमा होता है. इस जमा राशि पर हर साल ब्याज भी मिलता है, जो समय के साथ कंपाउंडिंग के जरिए एक बड़ा फंड तैयार कर देता है. यही पैसा रिटायरमेंट के

समय आर्थिक सहारा बनता है.

इसके अलावा, पीएफ का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है. तय शर्तें पूरी होने पर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिल सकती है, जो नियमित आय का स्रोत बनती है.

पीएफ योजना में बीमा सुरक्षा का लाभ भी मिलता है. कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत यदि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है, वह भी बिना किसी अलग प्रीमियम के. जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस राशि भी निकाल सकते हैं. यह सुविधा घर खरीदने, गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य जरूरी परिस्थितियों में उपलब्ध होती है.

> आज के समय में ईपीएफओ की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. जैसे बैलेंस चेक करना, पासबुक डाउनलोड करना, केवाईसी अपडेट करना और नॉमिनी जोड़ना—ये सभी काम अब घर बैठे किए जा सकते हैं. पीएफ सिर्फ सैलरी से कटने वाली रकम नहीं है, बल्कि यह बचत, पेंशन, बीमा, टैक्स लाभ और आपातकालीन सहायता का पूरा पैकेज है. इसलिए हर कर्मचारी को समय-समय पर अपना पीएफ खाता जरूर जांचना चाहिए और इसे लंबे समय तक सुरक्षित निवेश के रूप में बनाए रखना चाहिए

अनपढ़ महिला अल्बीना एक्का बनी सफल बिजनेस वुमन

रांची (झारखंड), 3 जुलाई मेहनत और हौसले के आगे शिक्षा की कमी भी बाधा नहीं बन सकती—इस बात को झारखंड की राजधानी रांची के पास पलांडू गांव की रहने वाली अल्बीना एक्का ने सच कर दिखाया है.

पढ़ना-लिखना न जानने के बावजूद उन्होंने चीकू की खेती से एक सफल बिजनेस खड़ा किया है और आज वह एक प्रेरणादायक महिला उद्यमी बन चुकी हैं.

अल्बीना एक्का के पास करीब 2 एकड़ जमीन है, जिसे उन्होंने सरकार की योजना के तहत लीज पर लिया है. इसी जमीन पर उन्होंने लगभग 2000 चीकू के पौधे लगाए, जो अब बड़े पेड़ों में बदल चुके हैं. आज उनकी खेती से हर दिन करीब एक टन चीकू का उत्पादन होता है, जिसकी सप्लाई झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अन्य राज्यों में की जाती है. वे बताती हैं कि उनकी फसल की गुणवत्ता काफी अच्छी है क्योंकि वे पूरी तरह ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हैं. इस खेती में लगभग 25 लोग नियमित रूप से काम करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है.

क्यूबीई बनी राहेजा क्यूबीई की एकमात्र मालिक

मुंबई, 3 जुलाई 2026 ऑस्ट्रेलिया की वैश्विक बीमा कंपनी इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड ने भारतीय बीमा कंपनी राहेजा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बची हुई हिस्सेदारी भी खरीद ली है. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनी का 100 प्रतिशत स्वामित्व क्यूबीई के पास है.

यह अधिग्रहण प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के साथ 18 वर्षों की संयुक्त भागीदारी के बाद पूरा हुआ है. इस बदलाव के साथ राहेजा क्यूबीई का नाम बदलकर केवल क्यूबीई कर दिया जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह कदम भारत में उसके दीर्घकालिक विस्तार और विकास की रणनीति का महत्वपूर्ण

हिस्सा है. कंपनी के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व मिलने के बाद उसे नए बीमा उत्पाद विकसित करने, आधुनिक तकनीक अपनाने, वैश्विक स्तर की कार्यप्रणालियों को लागू करने और परिचालन में नवाचार करने के अधिक अवसर मिलेंगे. इसका उद्देश्य भारतीय ग्राहकों को बेहतर, सरल और ग्राहक-केंद्रित बीमा सेवाएं उपलब्ध कराना है.

क्यूबीई एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉब कोसोवा ने कहा, 'भारत दुनिया के सबसे गतिशील बाजारों में से एक है. हमें विश्वास है कि क्यूबीई की वैश्विक विशेषज्ञता और क्षमताओं के साथ हम यहां विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने और इस विशाल बाजार की दीर्घकालिक संभावनाओं का लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में हैं.'

> **क्यूबीई एशिया के बारे में**
> क्यूबीई एशिया, क्यूबीई इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड के अंतरराष्ट्रीय कारोबार का हिस्सा है. कंपनी का मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज में सूचीबद्ध है. क्यूबीई दुनिया के कई देशों में सामान्य बीमा और पुनर्बीमा सेवाएं प्रदान करती है.

भारत से डोनाल्ड ट्रंप ने कमाए 81 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 3 जुलाई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कमाई में भारत का भी बड़ा योगदान सामने आया है. अमेरिकी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स की वित्तीय खुलासा रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने वर्ष 2025 में भारत से करीब 8.5 मिलियन डॉलर (लगभग 81 करोड़ रुपये) की आय अर्जित की. यह कमाई किसी प्रत्यक्ष निवेश या निर्माण कार्य से नहीं, बल्कि उनके नाम और ब्रांड के इस्तेमाल के बदले मिलने वाली लाइसेंस फीस से हुई.

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की कुल अनुमानित संपत्ति लगभग 5.7 अरब डॉलर है. वर्ष 2025 के दौरान उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी, रियल एस्टेट,

लाइसेंसिंग समझौतों और निवेश सहित विभिन्न स्रोतों से 2.2 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की. इनमें भारत उनके अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट लाइसेंसिंग कारोबार के प्रमुख बाजारों में शामिल रहा.

भारत में ट्रंप ऑर्गनाइजेशन का कारोबार अमेरिका से अलग मॉडल पर चलता है.

भारतीय शेयर बाजारों में तेजी जारी

262 अंक की बढ़त पर रहा सेंसेक्स

95.15 अंक से आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 03 जुलाई दूसरे एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 262 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ.

सेंसेक्स की शुरुआत 650 अंक चढ़कर हुई थी, लेकिन वह उस स्तर पर अंत तक टिक नहीं सका. कारोबार की समाप्ति पर

सूचकांक पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में 261.79 अंक (0.34 प्रतिशत) ऊपर 77,763.91 अंक पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 95.15 अंक यानी 0.39 प्रतिशत चढ़कर 24,270.85 अंक पर बंद हुआ. दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार तीसरे दिन मजबूत हुए हैं.

वृहत बाजार में मिलाजुला रुख रहा. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.13 फीसदी गिर गया जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.04 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. आईटी, फार्मा, रियल्टी और स्वास्थ्य सेक्टरों में अच्छी लिवाली देखी गयी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ऑटो और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों की कंपनियों में बिकवाली का जोर रहा. सेंसेक्स की कंपनियों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर पौने छह फीसदी और बजाज फिनसर्व का दो प्रतिशत से अधिक चढ़ गया.

अहमदाबाद में अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर शुरू

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने किया उद्घाटन

तकनीकी एकीकरण एवं दक्षता की दिशा में ऐतिहासिक कदम

अहमदाबाद, 3 जुलाई. यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध एवं विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने तथा रेल परिचालन को अत्याधुनिक तकनीक से सुदृढ़ बनाने की दिशा में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

अहमदाबाद मंडल में नवनिर्मित स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का आज मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया. यह अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र अब पूर्ण रूप से कार्यशील हो गया है और उत्तर गुजरात क्षेत्र में रेल संचालन के 'केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करेगा. लगभग 24,500 वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित यह आधुनिक परिसर रेल परिचालन से जुड़े विभिन्न विभागों की नियंत्रण गतिविधियों को एक ही छत के नीचे एकीकृत करता है. इसके माध्यम से परिचालन दक्षता, समयपालन तथा यात्री सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित होगा. उद्घाटन के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि अहमदाबाद मंडल निरंतर आधुनिक तकनीकों को अपनाकर भारतीय रेल के डिजिटल परिवर्तन को गति दे रहा है. उन्होंने कहा कि यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

रेनो ने क्विड का नया संस्करण पेश किया

नयी दिल्ली, 03 जुलाई फ्रांसीसी वाहन निर्माता रेनो ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेनो इंडिया ने शुक्रवार को नयी रेनो क्विड बाजार में उतारने की घोषणा की.

नाम सुधार सूचना

मै जग्गी लाल गुप्ता पिता श्री मोती लाल गुप्ता ग्रा./पो.-हनुमना, जिला-मऊगंज (म.प्र.) का निवासी हूं, मै भा.जी.बी.नि. से पालिसी नम्बर 375077402 बीमा लिया था, जिसमें त्रुटिवश मेरा नाम जग्य लाल गुप्ता हो गया था, जबकि हमारे समस्त दस्तावेजों में जग्गी लाल गुप्ता है. अतः समस्त दस्तावेजों के आधार पर हमे जग्गी लाल गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना जाए.

भवदीय
जग्गी लाल गुप्ता
तनय श्री मोती लाल गुप्ता

समाचार विशेष

पेज एक का शेष

रिपोर्ट से पहले ही यूसीसी विधेयक तैयार

इस कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक के बाद यूसीसी के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है. अब इसे मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी की गई है, लेकिन यह कमेटी की चेयरपर्सन की ओर से मिले समय पर तय होगा. बताया जा रहा है कि यदि चेयरपर्सन किसी कारणवश राजधानी भोपाल आने में असमर्थ रहीं तो कमेटी की ओर से रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह सहित कमेटी के अन्य सदस्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यूसीसी को लेकर तैयार सिफरिशें सौंप देंगे. धर्म बदलने वाले आदिवासी अब आदिवासी नहीं रहेंगे: देश के कई राज्यों के साथ ही मप्र में तेजी से धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं. विशेष रूप से सनातन धर्म के मानने वालो को टारगेट किया जा रहा है. इसमें भी आदिवासी समुदाय को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है. पैसों सहित अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय को विशेष रूप से इसाई धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं.

सरकार के पास ऐसा कोई मैकेन्जिम नहीं है, जो कि सीधे तौर पर इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित कर सके, धर्म परिवर्तन से जनजाति समाज अपनी परंपरा से दूर हो रहे हैं और चर्च के करीब जा रहे हैं. इसे रोकने के लिए यूसीसी बिल में कड़े प्रावधान किए जाने के संकेत हैं. बिल में किए गए प्रावधानों के मुताबिक धर्म बदलने वाले आदिवासी अब आदिवासी नहीं रहेंगे. वैसे तो यूसीसी बिल के प्रावधान जनजाति वर्ग पर लागू नहीं होंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन करने वालों पर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा. ऐसा करने से धर्म बदलने वालों को जनजाति समाज को मिलने वाली विशेष रियायतें नहीं मिलेंगी. वे आरक्षण के दायरे से बाहर हो सकते हैं, उन्हें अन्य सामान्य वर्ग की तरह ही माना जाएगा.

अमित शाह या नीतीश हो सकते हैं उप प्रधानमंत्री

इतना ही नहीं पिछले कुछ दिनों से जदयू के दूसरे क्रम के कई नेता नीतीश कुमार के अनुभवों को आधार बनाकर उन्हें उपप्रधानमंत्री बनाने की वकालत भी कर रहे हैं. इस संदर्भ में राजनीतिक जानकार यह भी कह रहे हैं कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय बड़े प्रदेश से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री या उपप्रधानमंत्री नहीं बना है ऐसे में संभव है कि गठबंधन सहयोगियों के बीच एक मजबूत और विश्वसनीय संदेश को स्थापित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय व राजनीतिक संतुलन को स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी कोई अप्रत्याशित फैसला कर लें. जानकार बता रहे हैं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास गवाह है कि उप-प्रधानमंत्री का पद हमेशा गठबंधन को बचाए रखने या पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन साधने के लिए दिया गया है. 1989 में वी.पी. सिंह सरकार में चौधरी देवीलाल और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लालकृष्ण आडवाणी को यह पद दिया गया था. वाजपेयी-आडवाणी के दौर में आडवाणी को उपप्रधानमंत्री बनाना पार्टी के भीतर उनके कद और उत्तराधिकार की स्पष्ट रेखा तय करना था. बहरहाल, उक्त सभी कयास और चर्चाएं दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में चल रहे गंभीर मंथन और वरिष्ठ नेताओं के तर्कसंगत विमर्श के बाद आरंभ हुई है.

डीएमके से और दूर हो रही है कांग्रेस

नई दिल्ली. ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी दशकों पुरानी सहयोगी डीएमके से दूरी बढ़ाती जा रही है. पहले तो चुनाव समाप्त होते ही उसने डीएमके से संबंध समाप्त किया और टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया.

टीवीके प्रमुख विजय ने कांग्रेस को सरकार में शामिल किया और इस तरह तमिलनाडु में कांग्रेस का 60 साल का सत्ता का सूखा समाप्त हुआ. इसके बाद डीएमके ने कांग्रेस से संबंध विच्छेद करने का ऐलान करते हुए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और लोकसभा में अलग बैठने की जगह मांगी. हालांकि इसके बावजूद कई लोगों को उम्मीद थी कि अगले कुछ दिन में डीएमके और कांग्रेस फिर साथ होंगे. हाल के घटनाक्रम से ऐसा नहीं लग रहा है.

कांग्रेस ने एक तरह से डीएमके और उसके प्रमुख एमके स्टालिन को चिढ़ाते हुए अपने सांसद मणिक्कम टैगोर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है. मणिक्कम टैगोर और स्टालिन का मामला वैसा ही है, जैसा बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी का है. विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे से पहले स्टालिन चाहते थे कि राहुल अपने नजदीकी मणिक्कम टैगोर को चुप कराएं और वार्ता से दूर रखें.

> असल में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने भांप लिया है कि दक्षिण भारत में उसका समय आ रहा है. दक्षिण के पांच बड़े राज्यों में से तीन में उसका मुख्यमंत्री बन गया है. चौथा राज्य तमिलनाडु हो सकता है. क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि वहां द्रविड राजनीति समाप्त हो रही है और डीएमके व अन्ना डीएमके दोनों हाशिए में जाएंगे. नई ताकतें उभरेंगी. विजय के अलावा अन्नामलाई भी मजबूत होंगे. ऐसे में कांग्रेस भी अपनी जगह नए सिरे से बना सकती है.

विशेष | **राजनीति से दूर नवजोत सिंह सिद्धू भी लड़ सकते हैं चुनाव**

चुनाव को लेकर कांग्रेस-बीजेपी ने बढ़ाई सक्रियता

चंडीगढ़. पंजाब में पिछली हार से सबक लेते हुए कांग्रेस चुनावों से पहले गुटबाजी खत्म करने में जुटी है. चर्चा है कि गुटबाजी से परेशान कांग्रेस हाईकमान पंजाब की पूरी लीडरशिप टीम को बदलने पर विचार कर रहा है. राहुल गांधी ने इसके लिए पंजाब के शीर्ष 5 नेताओं के साथ वन-टू-वन बैठकें की हैं.

कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता के बीच चर्चा सामने आई है कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू से फिर सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं. चर्चा यह है कि वह निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. पिछले दिनों उनकी पत्नी नजवोत कौर सिद्धू ने एक पार्टी बनाने के संकेत दिए थे, हालांकि इसके बाद कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

ऐसे में जब कांग्रेस पंजाब में अपने

पारंपरिक कोर वोट बैंक को वापस पाने के लिए दलित-अल्पसंख्यक एकता पर फोकस कर रही है. पार्टी इन दोनों समुदायों को जोड़कर एक नया चुनावी समीकरण बनाने की कोशिश में है. तब राजनीतिक हलकों में यह अटकलें सामने आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू फिर कांग्रेस के जरिए ही सक्रिय हो सकते हैं. नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर हैं, हालांकि वह जब अप्रैल 2023 में पटियाला जेल से जब रिहा हुए थे तब सिद्धू ने कहा था. जब भी इस देश में तानाशाही आई है, तब-तब एक क्रांति भी आई है और आज उस क्रांति का नाम राहुल गांधी है.

> **सिद्धू के बारे में क्या चर्चा?**
> पंजाब चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज होने के साथ चर्चा सामने आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं. उम्मी जताई जा रही है कि एक बार फिर वह कांग्रेस ज्वाइन करके ही राजनीति करें. अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है. नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आने से पिहले लंबे वक्त पर बीजेपी में रहे थे.

कार्यालय जनपद पंचायत कुसमी, जिला सीधी (म.प्र.)

क्रमांक/ /ज.पं/2026 कुसमी, दिनांक .....

विज्ञप्ति

जनपद पंचायत कार्यालय एवं क्षेत्रान्तर्गत देवरी सिचाई जलाशय (रकवा 68.660) को मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट हेतु शासन द्वारा निर्धारित पट्टा राशि पर 10 दस वर्षीय पट्टे पर आवंटित किया जाना है जिसके लिए स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति मछुआ समूहो एवं स्व सहायता समूहो से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति मछुआ समूहो एवं स्व सहायता समूह जनपद पंचायत कार्यालय में दिनांक 03.07.2026 से 21.07.2026 तक कार्यालयीन समय शायं 06.00 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर) निविदा आवेदन पत्र बंद लिफाफे में निविदा जमा कर सकते है, निविदा की शर्ते कार्यालय में देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुसमी
जिला सीधी (म.प्र.)

In The Court of II Additional Judge to 1 Civil Judge Junior Division, District Court, Satna
Presiding Officer : **श्री पूजित कमल**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/1400068/2016)

भागवत सिंह ....**वादी**
Vs
रामाधार सिंह ..... **प्रतिवादी**
Process Id-76/2026 **पेशी दिनांकः-27.07.2026**

प्रेषिती-
(1) श्रीमती सुधा सोनी पत्नी श्री रामनाथ सोनी पता-निवासी बाघवगढ़ कालोनी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

यह कि प्रार्थी **भागवत सिंह** ने आपके विरूद्ध **आरसीएसए** के लिये वाद संस्थित किया है. आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के **30 दिवस** के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 23 जून 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है.

(पूजित कमल)
न्यायालय की मुद्रा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सतना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना जिला सतना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग मऊगंज जिला मऊगंज (म0प्र0)

राजीव लोचन सिंह पिता गोविन्द सिंह, वीरेन्द्र सिंह पिता गोविन्द सिंह, रणजीत सिंह पिता गोविन्द सिंह सा0 नईगढी नहसील नईगढी जिला मऊगंज म0प्र0 .....**आवेदकगण**

बनाम

कमलेश कुमार पटेल पिता जीवन प्रसाद पटेल सा0 टटिहरा तहसील नईगढी जिला मऊगंज, शासन म0प्र0 ...**अनावेदगकगण**

समाचार पत्र के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के न्यायालय में आवेदक राजीव लोचन सिंह पिता गोविन्द सिंह बगैरह तहसील नईगढी जिला मऊगंज के द्वारा ग्राम नईगढी की भूमि खसरा न0 2888/1 रकबा 0.057 हे0 में खसरा सुधार किए जाने हेतु संहिता की धारा 115 के तहत इस न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। जो दिनांक 16.7.26 को सुनवाई हेतु नियत है।

अतः समस्त अनावेदकगण या अन्य हितबद्ध पक्षकार को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में नियत दिनांक 16.7.26 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग मऊगंज
जिला मऊगंज (म.प्र.)